*भारत के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक**

व्यापक, समावेशी और धारणीय वृद्धि के लिए बृहत्तर वित्तीय समावेशन (एफआई) महत्वपूर्ण है। इसलिए, एफआई को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई नीतिगत पहल की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए एफआई का एक महत्वपूर्ण कदम आवश्यक है। 97 संकेतकों पर आधारित एक बहुआयामी समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) का निर्माण किया गया है जो वित्तीय समावेशन को परिमाणित करता है और उपलब्धता, पहुंच में आसानी, उपयोग, असमान वितरण और सेवाओं में कमी, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। 0 से 100 के पैमाने में, 2021 के लिए गणना किए गए तीन उप-सूचकांक जैसे 'अभिगम', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' के साथ वार्षिक एफआई-इंडेक्स 53.9 पर रहा, जिसमें अभिगम उप-सूचकांक का 73.3 का मुख्य योगदान था। यह देश में वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अब तक संतोषजनक प्रगति को दर्शाता है जिसमें सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयास रहे हैं।

> *"हमें सभी के लिए धारणीय भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बृहत्तर वित्तीय समावेशन के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए"*
>
> श्री शक्तिकांत दास, जुलाई 2021[1]

I. भूमिका

वित्तीय अभिगम पहुंच को हमेशा आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक माना गया है, और इसलिए, एक समावेशी वित्तीय प्रणाली का संवर्धन नीतिगत वृद्धि और प्राथमिकता का एक क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, देश की मुख्यधारा की वित्तीय समावेशन यात्रा को 1950 के दशक में सहकारी समितियों के संवर्धन, 1960 के दशक में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों और आबादी के पिछड़े वर्गों को क्रेडिट देने के बारे में पता लगाया जा सकता है। अनेक वर्षों में शाखाओं के नेटवर्क का विस्तार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल), अग्रणी बैंक योजना का शुभारंभ, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) का संवर्धन, कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के कार्यान्वयन जैसी विभिन्न पहलों के साथ-साथ किया गया था। बीसी मॉडल द्वारा पूरित पारंपरिक भौतिक शाखाओं ने देश के कोने-कोने में बैंकिंग प्रणाली की पहुंच का विस्तार किया है। हालांकि, एफआई की दिशा में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के शुभारंभ के साथ अपने विभक्ति बिंदु तक पहुंच गया था, जिसके तहत अब तक अपवर्जित आबादी के खाते बड़ी संख्या में समयबद्ध तरीके से खोले गए थे, और समय के साथ हालिया वर्षों में डिजिटल माध्यम को बढ़ावा दिया गया और अपनाया गया।

जन-धन, आधार और मोबाइल (जेएएम) पारिस्थितिकी तंत्र ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया है और सुविधाजनक, संरक्षित और सुरक्षित, पारदर्शी और किफायती तरीके से डिजिटल भुगतान को सार्वभौमिक बनाने के लिए कई पहल की गई हैं। पिरामिड के निचले भाग में मूल्य के दोहन की अव्यक्त संभाव्यता को देखते हुए, बड़ी संख्या में भागीदार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं जैसे भुगतान बैंक, छोटे वित्त बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) और फिनटेक कंपनियां शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान देते हुए और वित्तीय सेवाओं के जिम्मेदार और धारणीय उपयोग करने के लिए ग्राहकों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था और आबादी के पिछड़े वर्गों की जरूरतों को पूरा करने पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति 2019-2024 (एनएसएफआई) और वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 (एनएसएफई) वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक समन्वित दृष्टिकोण के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है।

---

* यह आलेख अनिल कुमार शर्मा, कार्यपालक निदेशक; सोनाली सेनगुप्ता, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक; इंद्रजीत रॉय, निदेशक; और सुष्मिता फुकन, महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा 15 जुलाई, 2021 को इकोनॉमिक टाइम्स फ़ाइनेंशियल समिट में उद्घाटन भाषण दिया गया।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समेकित प्रयासों के साथ, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नीतिगत पहलों की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय समावेशन का एक समेकित उपाय आवश्यक है। इसलिए, एक वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) का निर्माण करना उचित है जो वित्तीय समावेशन को परिमाणित करता है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में उपलब्धता, पहुंच में आसानी, उपयोग की सीमा, सेवाओं में असमानता और कमी, वित्तीय साक्षरता का प्रसार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उत्तरदायी है; सुरक्षा; और बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेंशन क्षेत्र के विस्तार पर प्रकाश डालता है।

अक्टूबर 2017 में भारत सरकार द्वारा एक कार्य बल (टीएफ) का गठन किया गया था, जिसमें वित्तीय समावेशन के सूचकांक के निर्माण के लिए विभिन्न आयामों और पहलुओं का सुझाव देने के लिए सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व किया गया था। इस कार्य बल ने अगस्त 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जबकि कार्य बल द्वारा सुझाई गई कार्यप्रणाली को बरकरार रखा गया था, *अन्य बातों के साथ*, विभिन्न उप-सूचकांकों के तहत कई संकेतक जोड़े गए थे और भार वितरण, लक्ष्य मूल्य, *आदि* का निर्धारण करने के अलावा, 'गुणवत्ता' का एक आयाम पेश किया गया था।

तदनुसार, यह आलेख एफआई-सूचकांक के निर्माण में 'अभिगम', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' आयामों, भार वितरण, चयनित संकेतकों के लिए वांछित लक्ष्य, और इन संकेतकों को एक समग्र सूचकांक में संयोजित करने की पद्धति पर ज़ोर देता है। इस प्रकार निर्मित एफआई-सूचकांक 0 और 100 के बीच एक ही संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न आयामों पर जानकारी प्राप्त करता है - जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण का प्रतिनिधित्व करता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को इंगित करता है।

आलेख को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II वित्तीय समावेशन पर कुछ मौजूदा अध्ययनों की समीक्षा करता है। खंड III एफआई-सूचकांक के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली पर चर्चा करता है। खंड IV डेटा और परिणामों का वर्णन है; और खंड V आगे चलकर क्या क्रियाविधि होगी- इस पर ध्यान केन्द्रित करता है।

II. साहित्यिक समीक्षा

अधिकांश अध्ययनों ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण का पालन किया जिसमें प्रति व्यक्ति बैंक खाते, बैंक शाखाएं, एटीएम, क्रेडिट/ डेबिट कार्ड, घरेलू जमाकर्ताओं/ उधारकर्ताओं की संख्या शामिल थी (सरमा 2012; डबला-नोरिस *और अन्य*, 2015; मियालौ *और अन्य*, 2017)। एकल संकेतक दृष्टिकोण वित्तीय समावेशन की सही सीमा का सही वर्णन नहीं कर सकता है, उदाहरण के लिए, केवल एक बैंक खाता होने का मतलब यह नहीं हो सकता है कि भौतिक या मनोवैज्ञानिक बाधाओं के कारण खाते का अच्छी तरह से उपयोग किया गया है। इसके अलावा बैंक खाता होने के बावजूद "सीमांत बैंकिंग सुविधायुक्त" लोग औपचारिक वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त उपयोग नहीं कर रहे हैं और अनौपचारिक गैर-बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं (डिनिज *और अन्य*, 2011; केम्पसन, 2004; सीडमैन *और अन्य*, 2005)।

संस्थागत स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का वित्तीय अभिगम सर्वेक्षण (एफएएस) दुनिया भर में आधारभूत वित्तीय सेवाओं के उपयोग और उपयोग पर वार्षिक समय श्रृंखला डेटा एकत्र करता है। वित्तीय समावेशन के तहत प्रमुख अभिगम और उपयोग संकेतकों पर आपूर्ति पक्ष डेटा को समेटने के लिए एफएएस को 2009 में लॉन्च किया गया था। एफएएस, *अन्य बातों के साथ-साथ*, प्रति 100,000 व्यक्तियों पर एटीएम, प्रति 100,000 व्यक्तियों पर बैंक शाखाओं, प्रति 1000 वयस्कों पर जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं की संख्या, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जमा और क्रेडिट *आदि* के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह बीमा और डिजिटल लेनदेन पर डेटा भी प्राप्त करता है। एफएएस दुनिया के अधिकांश देशों के लिए वित्तीय समावेशन डेटा के व्यापक स्रोत के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग क्रॉस रेफरेंस के लिए किया जा सकता है। क्रिसिल का इनक्लूसिक्स, पहली बार 2013 में प्रकाशित होने के बाद अगली तीन बार 2014, 2015 और 2018 में प्रकाशित हुआ, एक समग्र सूचकांक है जो शाखा व्यापन (बीपी), ऋण व्यापन (सीपी), जमा व्यापन (डीपी) और बीमा व्यापन (आईपी) के चार आयामों में कुल छह मानकों के रूप में वित्तीय समावेशन को मापता है। 'इनक्लूसिक्स' जिले-वार आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर वित्तीय समावेशन का विस्तार करता

है। 2011 से विश्व बैंक प्रत्येक तीन साल में फाइंडेक्स डेटाबेस (डेमिरगुक-कुंट और क्लैपर, 2012) प्रकाशित करता है जो 140 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 150,000 से अधिक वयस्कों के सर्वेक्षण पर आधारित है कि वयस्क कैसे बचत करते हैं, उधार लेते हैं, भुगतान करते हैं, और जोखिम का प्रबंधन करते हैं।

III. क्रियाविधि

एफआई-इंडेक्स के निर्माण में तीन प्रमुख चुनौतियां हैं, *अर्थात*, उपयुक्त संकेतक या चर का चयन, लक्ष्य निर्धारित करना (वांछित स्तर), और भार वितरण का निर्धारण करना।

एफआई-सूचकांक पर अधिकांश मौजूदा अध्ययन वित्तीय समावेशन की पहुंच और उपयोग आयाम का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर सामान्यीकृत संकेतकों के भारित औसत (या समान भार) के आधार पर एक समग्र सूचकांक का निर्माण करते हैं। हालांकि, ये अध्ययन वित्तीय समावेशन के 'गुणवत्ता' आयाम को छोड़ देते हैं, जो वित्तीय समावेशन को कारगर बनाने के उद्देश्य की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चूंकि चयनित संकेतकों को संयोजित करने से पहले उन्हें समान पैमाने पर लाने के लिए सामान्यीकृत करने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक संकेतक की तुलना उसके वांछित लक्ष्य के संबंध में की जाती है; जब कोई संकेतक अपने वांछित लक्ष्य या 'इष्टतम मूल्य' को प्राप्त करता है; यह माना जाता है कि संकेतक द्वारा अनुमानित वित्तीय समावेशन पूरा हो गया है। चूंकि सैद्धांतिक रूप से वित्तीय समावेशन के एक संकेतक के लिए उपलब्धि के इष्टतम स्तर तक पहुंचना मुश्किल है, लक्ष्य मूल्य को तय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

इसके अलावा, सभी चयनित संकेतकों का वित्तीय समावेशन लक्ष्य के प्रति समान महत्व नहीं हो सकता है। इसलिए, चयनित संकेतकों के बीच भार वितरण असमान हो सकता है और बहिर्जात रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित एफआई-सूचकांक वित्तीय समावेशन के तीन आयामों पर आधारित है, *अर्थात* 'पहुंच', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' जिनका भार क्रमशः 35, 45 और 20 प्रतिशत है। वित्तीय समावेशन ('उपयोग' और 'गुणवत्ता') के गहन पहलू के लिए उच्च भार के साथ सूचकांक को दूरंदेशी बनाने के लिए भार निर्धारित किए गए थे।

एफआई को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सूचकांक के तीन आयामों के संकेतक, उनके इष्टतम मूल्य और उनके संबंधित भार संबंधित क्षेत्रवार विनियामकों और सरकार के परामर्श से तय किए गए थे।

मोटे तौर पर, कुल भार का एक तिहाई भाग 'पहुंच' को निर्दिष्ट किया गया है जिसमें पूर्व में अधिकांश पहलें की गई हैं और जो उपलब्ध कराए गए आपूर्ति पक्ष के वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर की सीमा को दर्शाता है। दो-तिहाई भार वित्तीय समावेशन के गहन पहलू *अर्थात* 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' को सौंपा गया है। इन तीन उप-सूचकांकों में से प्रत्येक संकेतक, गैर-अतिव्यापी समूह के आधार पर गणना किए गए आयामों के अलग-अलग समूहों से बना है।

'अभिगम' उप-सूचकांक, जिसे आगे चार आयामों में विभाजित किया गया है, *जैसे*, 'बैंकिंग', 'डिजिटल', 'पेंशन' और 'बीमा', वित्तीय समावेशन के आपूर्ति पक्ष पर किए गए प्रयासों को दर्शाता है, जैसे कि भौतिक और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और अपवर्जित वर्गों के लिए आधारभूत उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने के तरीके। चार आयामों में 26 संकेतकों को बीसी, एनबीएफसी, और डाकघर *आदि* सहित बैंकिंग आउटलेट की संख्या, अल्प बचत सहित कुल बचत खातों की संख्या, सभी प्रकार के कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर, जेएएम पारिस्थितिकी तंत्र, विभिन्न पेंशन योजनाओं और कार्यालयों और जीवन और गैर-जीवन बीमा आदि के एजेंटों का सदस्यता आधार प्राप्त करने के लिए चुना गया है।

'उपयोग' उप-सूचकांक पांच आयामों में विभाजित है, *अर्थात*, 'बचत और निवेश', 'क्रेडिट', 'डिजिटल', 'बीमा' और 'पेंशन'। यह मांग पक्ष का उपाय 52 संकेतकों से मिलकर बना है और बचत, निवेश, बीमा, ऋण और विप्रेषण सुविधाओं *आदि* के माध्यम से वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के सक्रिय उपयोग के विस्तार को दर्शाता है। संकेतक बचत और निवेश स्वभाव को प्रतिबिंबित करने, बैंकों और गैर-बैंकों से ऋण प्राप्त करने, खुदरा डिजिटल भुगतानों का उपयोग, जीवन और गैर-जीवन दोनों बीमा की पहुँच, और विभिन्न पेंशन योजनाओं में योगदान के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

'गुणवत्ता' उप-सूचकांक के तीन आयाम हैं,अर्थात, 'वित्तीय साक्षरता', 'उपभोक्ता संरक्षण', और 19 संकेतकों के साथ वित्तीय वितरण फ्रेमवर्क में 'असमानता'। ये संकेतक नागरिकों को उपलब्ध उचित वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूक करने के लिए, उनका उपयोग करने के सुरक्षित तरीके, और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जैसे मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूक बनाने के हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों का पता लगाते हैं। वे शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को भी दर्शाते हैं और वित्तीय पहुँच और उपयोग के कुछ संकेतकों के असमान वितरण का हिसाब भी रखते हैं। असमानता को मापने के लिए ज़िला स्तरीय डेटा कणिकता के साथ लोरेंज वक्र पर आधारित गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है।

सूचकांक में 97 संकेतकों में से 90 प्राथमिक संकेतक हैं और शेष 7 संकेतक संबंधित सात प्राथमिक संकेतक की असमानता के उपाय हैं अर्थात बैंक शाखाओं का वितरण, निश्चित-बिंदु व्यापार आढ़तियों का वितरण (एफबीसी) आउटलेट, एटीएम का वितरण, बचत खाते की संख्या और बचत राशियों का वितरण, क्रेडिट खातों की संख्या का वितरण और बकाया ऋण। लोरेंज वक्र और असमानता के उपाय इन सातों के गिनी गुणांक के संदर्भ में मापे गए संकेतक अनुबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। सभी संकेतक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति के लिए जहां भी आवश्यक हो समायोजित किया जाता है।

समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक बनाने के लिए, कई शोध अध्ययनों ने इसी तरह की पद्धति का इस्तेमाल किया है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण में (एचडीआई) और मानव गरीबी सूचकांक (एचपीआई) में उपयोग किया जाता है। दृष्टिकोण एकाधिक संकेतकों को एक ही संख्या में संयोजित करने के लिए सरमा (2008) द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि के समान है जिसने यूएनडीपी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का अनुसरण किया था।

चयनित संकेतकों को सम्मान के साथ सामान्यीकृत किया गया उस मामले में जब कोई वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए, एफ़आई-सूचकांक का कोई 'आधार वर्ष' नहीं होता है। न्यूनतम मूल्य एक सामान्यीकृत पैरामीटर का '0' है और उच्चतम मान '100' है। सभी संकेतक वाईआई सामान्यीकृत हैं एनआई, उन्हें इकाई मुक्त करने के लिए और उन्हें उसी पैमाने पर लाने के लिए, उन्हें संबंधित वांछित लक्ष्य से विभाजित किया जाता है। सभी संकेतकों के इच्छित लक्ष्य (टी$_{\text{आई}}$) और संकेतकों के भार वितरण के (डबल्यू$_{\text{आई}}$), आयाम, और उप-सूचकांक हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद पहुंचे थे। कुछ संकेतक अलग से जोड़े जाते हैं (जैसे, बीएसबीडीए, पीएमजेडीवाई खाते) कुल या समग्र व्यापक संकेतकों में एक समूह के रूप में उनकी निहित उपस्थिती के अलावा (कुल बचत खाते), वित्तीय समावेशन के लिए उनके महत्व को दर्शाने के लिए उन्हें भी चयनित संकेतकों में से एक के रूप में लिया जाता है। सभी आयामों के लिए वित्तीय समावेशन को भारित सामान्यीकृत संकेतक (डबल्यू$_1$एन$_1$, डबल्यू$_2$एन$_{2,}$.......डबल्यू$_{\text{के}}$एन$_{\text{के}}$) की सामान्यीकृत 'यूक्लिडियन दूरी' के औसत द्वारा मापा जाता है एन-आयामी क्षेत्र में उनके सबसे खराब बिन्दु (0,0,.....0) से उनके सबसे अच्छे बिन्दु (डबल्यू$_1$, डबल्यू$_2$, ... डबल्यू$_{\text{एन}}$) से दूरी के व्युत्क्रम में। एफ़आई उप-सूचकांक की गणना संबंधित आयाम के आधार पर की जाती है और एफ़आई-सूचकांक की गणना तीन उप-सूचकांकों के आधार पर की जाती है उसी पद्धति का अनुसरण करते हैं जैसा कि उपयोग किया जाता है आयामों की गणना करने के लिए।

मानो वाई$_{\text{आई,}}$ जहां $_{\text{आई}}$=1,2,...के, आई वाला सूचकांक, और डबल्यू$_{\text{आई}}$ संबन्धित भार है $_{\text{आई}}$ सूचकांक के लिए और टी$_{\text{आई}}$ इच्छित लक्ष्य है या निर्धारित लक्ष्य है $_{\text{आई}}$ सूचकांक के लिए। मानो एन$_{\text{आई}}$ एक सामान्यीकृत मान है आई वाले संकेतक के लिए वाई$_{\text{आई}}$ के समतुल्य।

$$\text{एन}_{\text{आई}} = \text{सामान्यीकृत मान (वाई}_{\text{आई}}\text{)} = \frac{\text{वाई}_{\text{आई}} - \text{जब कोई वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध नहीं थीं}}{\text{इच्छित लक्ष्य (टी}_{\text{आई}}\text{)}}$$

$$N_i = \frac{Y_i - 0}{t_i} = \frac{Y_i}{t_i}$$

$$Let\ d_i = w_i * N_i;\ d_i^2 = d_i * d_i;$$

$$Let\ D^2 = d_1^2 + d_2^2 + \cdots + d_k^2 = \sum_{i=1}^{k} d_i^2;$$

$$Let\ W^2 = w_1^2 + w_2^2 + \cdots + w_k^2 = \sum_{i=1}^{k} w_i^2 \text{ and}$$

$$(W - D)^2 = \sum_{i=1}^{k} (w_i - d_i)^2$$

$$\text{Let } X_1 = \frac{\sqrt{D^2}}{\sqrt{W^2}} \text{ and } X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(W-D)^2}}{\sqrt{W^2}}$$

$$\text{आयाम का एफ़आई सूचकांक} = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

IV. डेटा और परिणाम

2017-2021 की अवधि के लिए सभी संकेतकों के लिए वार्षिक आवृत्ति पर आवश्यक डेटा संबंधित क्षेत्रीय नियामकों से प्राप्त किया गया है।

2017 के लिए 43.4 के मुकाबले 2021 के लिए परिकलित वार्षिक एफ़आई-सूचकांक 53.9, संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 5.5 प्रतिशत दर्ज की गयी।

तीन उप-सूचकांकों में से, एफ़आई-अभिगम सूचकांक 73.3 के मान पर, अपेक्षित रूप से, दोनों एफ़आई-उपयोग (43.0) और एफ़आई-गुणवत्ता (50.7) की तुलना में अधिक है जो इंगित करता है अधिक वित्तीय समावेशन के लिए जो मूलभूत अंग वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप वर्षों में स्थापित किया गया है उसे वित्तीय संस्थान को गहरा करके 'उपयोग' को बढ़ावा देने और 'गुणवत्ता' में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से आगे बढ़ाने की जरूरत है।

अभिगम उप-सूचकांक: 1950 के दशक से और हाल ही में बड़ी संख्या में उपाय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्तीय सेवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करने में किया गया। तदनुसार, 26 में से 16 संकेतकों के 'अभिगम' के अंतर्गत सूचकांक मान 53.9 के समग्र सूचकांक मान से भी अधिक हैं, जिसके परिणामस्वरूप अभिगम उप सूचकांक मान 73.3 है, जो भारत के आकार के देश के लिए है और विविधता, सराहनीय प्रगति का संकेत देती है। इस मान काफी हद तक वर्षों में वृद्धि से प्रेरित है, और हाल ही में, मानवयुक्त बैंक आउटलेट्स की संख्या में स्वयं के कर्मचारियों द्वारा, एफ़बीसीएस, बचत खातों की कुल संख्या, डाकघर, म्यूचुअल फ़ंड में ग्राहकों की संख्या (एमएफ), जेएएम पारिस्थितिकी तंत्र, कार्यालयों की संख्या, बीमा, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता, और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल आदि की संख्या में वृद्धि के कारण हैं।

सारणी 1: एफआई-सूचकांक और उप-सूचकांक

वर्ष	अभिगम	उपयोग	गुणवत्ता	एफआई-सूचकांक
मार्च-17	61.7	30.8	48.5	43.4
मार्च-18	63.9	33.7	51.4	46
मार्च-19	67.5	38.7	52.6	49.9
मार्च-20	71.6	42	53.8	53.1
मार्च-21*	73.3	43	50.7	53.9

*कुछ डेटा बिंदु अनंतिम हैं।

चार्ट 1: 2017-21 के लिए 0-100 के पैमाने पर एफआई-सूचकांक

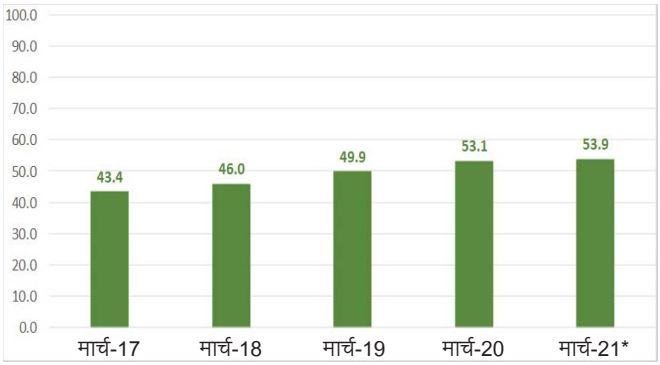

उपयोग उप-सूचकांक: उपयोग ने उच्चतम वृद्धि दिखाई है अन्य उप-सूचकांकों की तुलना में, मुख्य रूप से 'बीमा', 'क्रेडिट' और 'बचत और निवेश' द्वारा संचालित है। इन आयामों के तहत कुछ संकेतकों की पर्याप्त वृद्धि दर्शाई गई जिसमें कुल क्रेडिट खाते, क्रेडिट में बकाया राशि एकीकृत भुगतान के खाते इंटरफेस (यूपीआई) के मात्र और मूल्य लेनदेन शामिल हैं। विभिन्न सरकारों के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के बढ़े हुए उपयोग का भी बैंक के बचत खाते में अधिक बकाया राशि के माध्यम से सूचकांक मान पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

जबकि कुछ वर्षों में 'अभिगम' के तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है और यह अच्छा सूचकांक मान दिखा रहा है, इसकी संभवता कोविड-19 से संबन्धित प्रतिबंध के कारण 2021 में 'उपयोग' में गिरावट आई है। बीसी मॉडल, जो आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) चैनल का उपयोग करता है, इन प्रतिबंधों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत घोषित किए गए नकद लाभों की अंतिम छोर तक सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने के लिए सामने आया 94 करोड़ से अधिक लेनदेन के माध्यम से 2020-21 के दौरान ₹2.25 लाख करोड़ तक जो है।

गुणवत्ता उप-सूचकांक: क्रेडिट बकाया में क्षेत्रीय असमानता गिनी गुणांक के साथ 0.72 पर सबसे मुख्य है, इसके बाद जमा राशि में असमानता 0.58 के गिनी गुणांक के साथ। जमा खातों की संख्या के लिए गिनी गुणांक, एफ़बीसीएस, बैंक शाखाओं, क्रेडिट खातों, एटीएम की गणना क्रमश: 0.20, 0.25, 0.29, 0.43, 0.45 पर की जाती है (अनुबंध)।

V. आगे का रास्ता

एफआई-सूचकांक द्वारा मापी गई प्रगति, समावेशी प्रयास के मांग पक्ष पर अधिक से अधिक और केंद्रित हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। एनएसएफई ने एक वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण निर्धारित किया है। इसमें वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 सी' दृष्टिकोण शामिल है जिसमें शिक्षा प्रासंगिक सामग्री (स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के पाठ्यक्रम में शामिल); वित्तीय सेवाएं और शिक्षा प्रदान करने वाले बिचौलियों की क्षमता में सुधार करना; समुदाय आधारित मॉडल अपनाने के माध्यम से वित्तीय साक्षरता उपयुक्त संचार रणनीति के साथ; विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और बढ़ाना।

पीएमजेडीवाई कार्यक्रम की सफलता पर पहुंच प्रदान करने में, प्रसुप्त/निष्क्रिय खातों से संबन्धित समस्याओं जैसे अंतर्निहित कारकों जैसे पर्याप्त/नियमित आय की कमी, उपयुक्त वित्तीय उत्पाद का सृजन और उनसे संबन्धित जागरूकता की कमी को दूर करना, प्रक्रियात्मक/संचालन संबंधी चुनौतियां और उपलब्ध स्वीकृति इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, आदि को दूर करने की ज़रूरत है।

इस बात को समझना कि सतत वित्तीय समावेशन तक तभी पहुंचा जा सकता है जब वित्तीय सेवा प्रदाताओं तक पहुँच के साथ बीमा सहित वित्तीय उत्पादों का गुलदस्ता, पेंशन, निवेश और ऋण, एनएसएफआई, जैसी सुविधाएं दी जाएं, अर्थात, प्रत्येक इच्छुक और पात्र ग्राहक इस तरह कि सुविधाएं दी जाएँ। इस वित्तीय समावेशन के पहलू को और बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अलावा, एनएसएफआई जैसे मील के पत्थर के अनुसरण में वित्तीय साक्षरता केंद्रों की पहुंच का विस्तार करना (सीएफएल), चरण I में 1,199 सीएफएल को स्थापित करके सीएफ़एल की पायलट परियोजना को बढ़ाया जा रहा है।

वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में बीसी के प्रसार के अलग-अलग व्यवसाय मॉडल के साथ, वियोजित अंतिम मील को संबोधित करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बीसी एजेंटों की निरंतर उपलब्धता से संबंधित मुद्दे, उनकी क्षमता निर्माण, प्रमाणन आवश्यकताओं और पारिश्रमिक से संबंधित मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने की जरूरत है।

क्रेडिट अभिगम में आसानी, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), लघु और सीमांत किसान (एसएमएफ), महिलाएं और सूक्ष्म ऋण का खंड नीति निर्माताओं के लिए एक नीति प्राथमिकता बने हुए हैं। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के दिशानिर्देश में हालिया संशोधन पूरे देश में चिन्हित ऋण की कमी वाले जिलों को ऋण को प्रोत्साहन देने के फ्रेमवर्क के साथ, स्टार्टअप्स को शामिल करना, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़ोर आदि से ऋण के विनियोजन में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और लक्षित क्षेत्रों को अधिक से अधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने की उम्मीद की जा रही है।

अधिक वित्तीय संस्थाओं को बढ़ावा देने वाले डिजिटल लेनदेन के विस्तार और गहनता को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में 42 जिलों की पहचान की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये जिले आवश्यक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल साक्षरता के निर्माण के माध्यम से एक वर्ष में 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम हो जाएं। अन्य चिन्हित जिलों में पायलट के पैमाने पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।

अधिक वित्तीय समावेशन और बढ़ते डिजिटल लेनदेन के साथ, सेवाओं में कमी और असफल लेनदेन आदि के कारण उत्पन्न होने वाली शिकायतों का प्रभावी और शीघ्र निवारण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। जबकि सभी नियामकों द्वारा इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, प्रयासों को बढ़ाने और समन्वित करने की आवश्यकता है।

यह आशा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष जुलाई में रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एफ़आई -सूचकांक न केवल विभिन्न हितधारकों द्वारा पहले से किए गए और किए जा रहे उपायों की सफलता को दर्शाएगा, बल्कि आगे किए जाने वाले उपायों के संबंध में एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगा।

संदर्भ

Dabla-Norris, E., Y. Deng, A. Ivanova, I. Karpowicz, F. Unsal, E. VanLeemput, and J. Wong (2015). "Financial Inclusion: Zooming in on Latin America," IMF Working Paper 15/206, International Monetary Fund, Washington, D.C.

Demirguc-Kunt, A., and Klapper L. (2012). "Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database". Policy Research Working Paper 6025, The World Bank.

Diniz, E., Birochi, R. and Pozzebon, M. (2011). "Triggers and barriers to financial inclusion: The use of ICT-based branchless banking in an Amazon county". Electronic Commerce Research and Applications online at: http://dx.doi.org/10.1016/j.elerap.2011.07.006

Kempson E, Atkinson, A., and Pilley, O. (2004). "Policy level response to financial exclusion in developed economies: lessons for developing countries". Report of Personal Finance Research Centre, University of Bristol.

Mialou, A.,Amidzić, G., Massara, A. (2017)," Assessing Countries' Financial Inclusion Standing — A New Composite Index", Journal of Banking and Financial Economics, Central and Eastern European Online Library GmbH, Frankfurt, Germany.

Sarma, M. (2012). "Index of Financial Inclusion—A measure of financial sector inclusiveness", Competence Centre on Money, Trade, Finance and Development Working Paper No. 07/2012, Berlin.

Seidman, E., Hababou, M. and Kramer, J. (2005) "Getting to Know Underbanked Consumers: A Financial Services Analysis". Report of the Center for Financial Services Innovation, Chicago.

अनुबंध

चुनिंदा संकेतकों के लिए मापी गई असमानता